



BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

पीएमएवाई-जी: ग्रामीण भारत में सबके लिए आवास का प्रयास

मार्च 31, 2026

मुख्य बातें

- पीएमएवाई-ग्रामीण कार्यक्रम के पहले और दूसरे चरण के तहत, राज्यों को 4.15 करोड़ घर आवंटित किए गए, 3.90 करोड़ घर स्वीकृत किए गए, 2.99 करोड़ घर बनाए गए।
- वर्ष 2029 तक, कुल 4.95 करोड़ ग्रामीण घरों का लक्ष्य हासिल करना है।
- आवास लाभार्थियों को कुल 4,03,886.12 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं, जिससे देश भर में समय पर निर्माण सहायता सुनिश्चित हुई है।
- जियोटैगिंग, विसंगति का पता लगाने और आधार फेस प्रमाणीकरण जैसे एआई संचालित निगरानी उपकरण पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में सहायक हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जल जीवन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के साथ निर्बाध संयोजन ने ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाया है।

परिचय

पिछले एक दशक में देश में ग्रामीण आवास की यात्रा बदलाव और गरिमा की कहानी है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास एक सुरक्षित घर का लक्ष्य सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई यह योजना आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल गया है, इससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। पक्का घर सिर्फ एक आश्रय नहीं है बल्कि यह स्थिरता, अवसर और भविष्य के लिए आशा की नींव है।

1 अप्रैल 2016 से लागू की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण देश की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण पहलों में से एक के रूप में विकसित हुई है। इसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी (पक्का) घर प्रदान करना है। ग्रामीण आवास की कमी को दूर करके और आवास की खामियों को कम करके यह योजना "सभी के लिए आवास" के मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीएमएवाई-जी के तहत घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र भी शामिल है। अपने लक्ष्यों को उत्तरोत्तर प्राप्त करने के लिए इस योजना को कई चरणों में लागू किया गया है।

इस योजना ने स्वच्छता, खाना पकाने का स्वच्छ इंधन, बिजली और पेयजल तक पहुंच के साथ आवास को जोड़कर पूरे भारत के गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना ने प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ संयोजन को अपनाया है, जो समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है।

एक घर जिसने सब कुछ बदल दिया:

सुरक्षा और स्थिरता की ओर विधवा महिला ताइद की यात्रा

असम में जोरहाट जिले के तीताबोर इलाके की रहने वाली विधवा ताइद वर्षों तक बाढ़ प्रभावित इलाके में रहती थीं, जहां उनके घर को कोई कम सुरक्षा नहीं थी। जीवन अनिश्चित था, लेकिन 2016-17 में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के माध्यम से एक स्थायी घर का उनका सपना साकार हो गया। इस योजना के तहत मिली मदद से, उसने एक मजबूत घर बनाया जिससे उसके परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिला। आज, उनका स्थायी घर सुदृढ़ता के प्रतीक के रूप में खड़ा है, उसके परिवार को बाढ़ से बचाता है और भविष्य के लिए स्थिरता प्रदान करता है। ताइद की यात्रा दर्शाती है कि कैसे पीएमएवाईजी ग्रामीण जीवन को बदल रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सबसे कमजोर परिवार भी एक उज्ज्वल कल की ओर कदम बढ़ा सकता है।



प्रगति और उपलब्धियों का एक दशक

पिछले दस वर्षों में, पीएमएवाईजी ने लगातार अपनी पहुंच का विस्तार किया है और बड़े पैमाने पर आवास प्रदान किए हैं। इस योजना ने लगातार प्रदर्शन किया है, जिसमें वर्षवार पूर्णता विभिन्न चरणों में स्थिर प्रगति बनाए रखने की इसकी क्षमता का संकेत देती है। पीएमएवाईजी ने रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (पूर्ववर्ती मनरेगा), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वयं सहायता समूहों, जल जीवन मिशन और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए विकसित भारत-गारंटी के साथ निर्बाध संयोजन के माध्यम से लाभार्थियों को सशक्त बनाया है।

Total Houses Completed under PM Awaas Yojana – Gramin



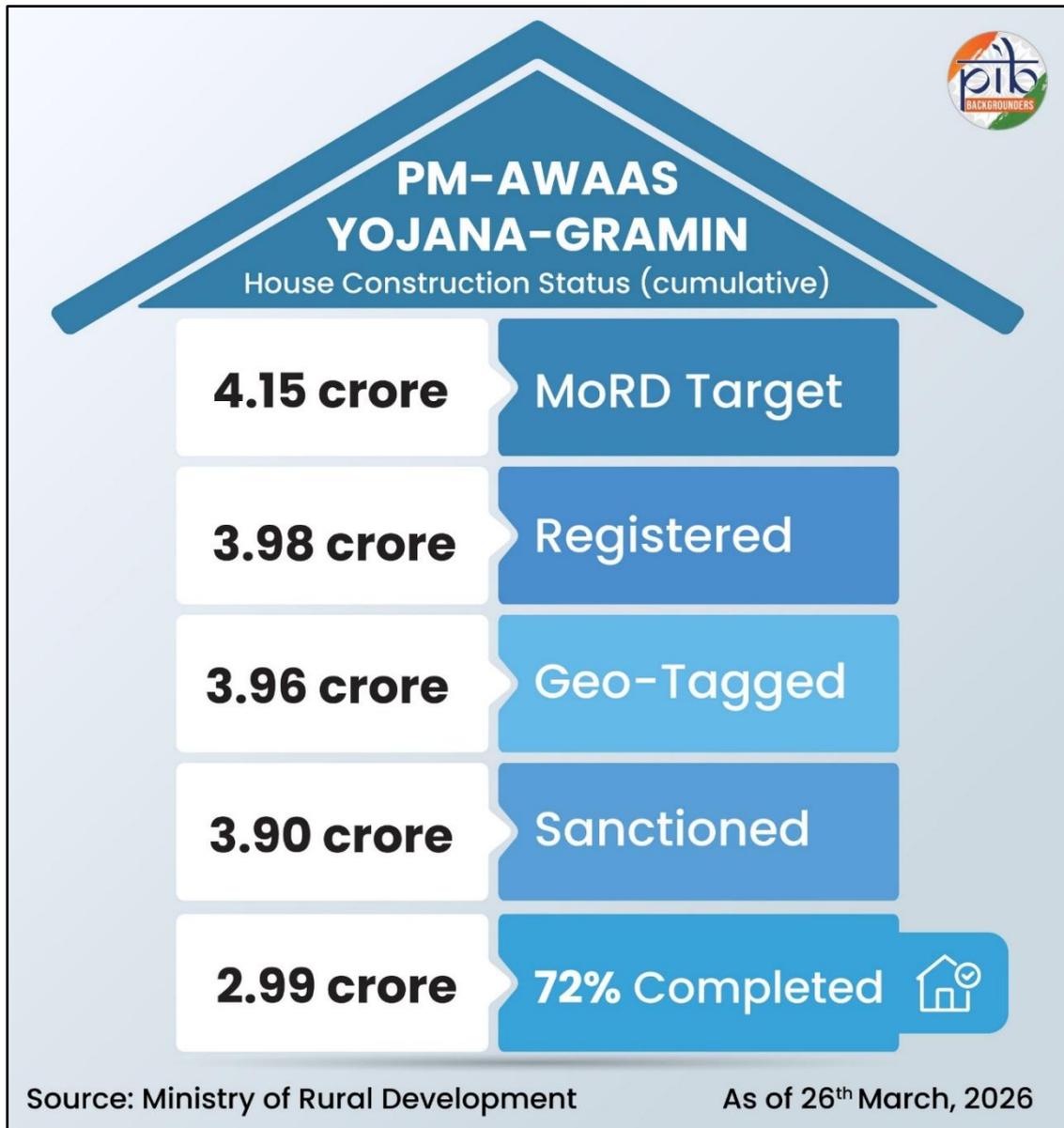
Financial Year	Houses Completed
2016-2017	2,115
2017-2018	38,15,966
2018-2019	44,92,951
2019-2020	21,31,192
2020-2021	33,99,570
2021-2022	42,39,725
2022-2023	57,74,696
2023-2024	20,83,730
Total	2,59,39,945
2024-2025	13,73,546
2025-2026	26,01,907
Total	2,99,15,398

Source: Ministry of Rural Development

आवंटित लक्ष्य और उपलब्धियां

26 मार्च 2026 तक, चरण I और II के तहत 4.15 करोड़ घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। कुल मिलाकर, 3.90 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, और 2.99 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। कार्यान्वयन के इस पैमाने का समर्थन करने के लिए, 4,03,886.12 करोड़ रुपये का संचयी निधि हस्तांतरण किया गया है, जिससे राज्यों में निर्माण और लाभार्थी सहायता के लिए समय पर संसाधन सुनिश्चित हुए हैं।

सामूहिक रूप से, ये उपलब्धियां पीएमएवाई-जी की निरंतर गति और व्यापक पैमाने पर प्रभाव को दर्शाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक आवास की ओर बढ़ने में इसकी प्रभावशीलता को उजागर करते हैं।



कार्यान्वयन ढांचा और सुधार

पीएमएवाईजी को एक लाभार्थी कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है, जहां परिवार अपने घरों के निर्माण का स्वामित्व लेते हैं। बीते वर्षों में, इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं।

1. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि धन बिना किसी देरी या गड़बड़ी के घर मालिकों तक पहुंचे, जिससे वित्तीय समावेशन मजबूत हो।
2. **घरों की जियोटैगिंग:** घर निर्माण के हर चरण में, समय और तारीख की मुहर लगी तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। इस डिजिटल रिकॉर्ड से निर्माण की प्रगति की वास्तविक समय की निगरानी होती है और यह सुनिश्चित होता है कि घर दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं।
3. **ग्राम स्तर के कार्यकर्ता:** प्रत्येक स्वीकृत घर को एक स्थानीय पदाधिकारी के साथ जोड़ा जाता है जो लाभार्थी के साथ आगे की कार्रवाई करता है। इस प्रणाली से व्यावहारिक सहायता प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित होता है कि निर्माण समय पर पूरा हो।
4. **ब्लॉक और जिला निरीक्षण:** ब्लॉक स्तर पर अधिकारी लगभग 10 प्रतिशत घरों का निरीक्षण करते हैं, जबकि जिला अधिकारी निर्माण के प्रत्येक चरण में 2 प्रतिशत का निरीक्षण करते हैं। ये निरीक्षण गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण की एक अतिरिक्त परत जोड़ते हैं।
5. **सामाजिक लेखा परीक्षा:** प्रत्येक ग्राम पंचायत वर्ष में कम से कम एक बार औपचारिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है। इसमें सामुदायिक भागीदारी और योजना के सभी पहलुओं की समीक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना शामिल है।
6. **राष्ट्रीय स्तर की निगरानी:** ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी और राष्ट्रीय स्तर के निरीक्षक क्षेत्र निरीक्षण के दौरान घरों का दौरा करते हैं। वे प्रगति का आकलन करते हैं, लाभार्थी चयन को सत्यापित करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जा रहा है।
7. **आवाससॉफ्ट (AwaasSoft) एमआईएस प्लेटफॉर्म:** आवाससॉफ्ट एक द्विभाषी, वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो पीएमएवाईजी के सभी कार्यों को एकीकृत करता है। लाभार्थी की पहचान और मंजूरी के आदेशों से लेकर निधि जारी करने और निर्माण निगरानी तक, यह सभी हितधारकों के लिए जानकारी का एक ही स्रोत प्रदान करता है।

इन सुधारों ने एक मजबूत ढांचा तैयार किया है जो प्रौद्योगिकी, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत निरीक्षण को जोड़ता है। इसने पीएमएवाईजी को पारदर्शी और कुशलता से आवास प्रदान करने में सक्षम बनाया है।

ग्रामीण परिवारों पर प्रभाव

इस योजना से ग्रामीण परिवारों ने सुरक्षित घर, बेहतर सेवाएं और सशक्तिकरण जैसे गहन परिवर्तन देखा है। पीएमएवाई-जी ने सामाजिक समावेश और आवश्यक वस्तुओं तक लोगों की पहुंच को सहज करके इन बदलावों को आगे बढ़ाया है।

- 1. रहन-सहन की स्थितियों में सुधार:** ग्रामीण परिवार अब स्थायी (पक्के) घरों में रहते हैं जो टिकाऊ, सुरक्षित और मौसम के दुष्प्रभावों से मुक्त हैं। अस्थायी (कच्चा) से स्थायी (पक्का) आवास में इस बदलाव ने लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा और सम्मान बढ़ाया है।
- 2. स्वच्छता तक पहुंच:** विभिन्न अन्य योजनाओं के साथ संयोजन के जरिए, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण [एसबीएम (जी)], मनरेगा (अब वीबी: जी राम जी) या किसी अन्य समर्पित धन स्रोत से 12,000 रुपये की सहायता मिलती है। इसने स्वच्छता को बढ़ावा दिया है, स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया है और गांवों को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया है।
- 3. रोजगार सहायता:** यह योजना मनरेगा (अब वीबी: जी राम जी) के तहत अकुशल श्रम मजदूरी के 90-95 मानव दिवस सुनिश्चित करती है। यह न केवल निर्माण का समर्थन करता है बल्कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करता है।
- 4. स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन:** प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ संयोजन ने ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन हासिल करने में सक्षम बनाया है। इससे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम हुई है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और स्वच्छ ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा मिला है।
- 5. बिजली और पानी की आपूर्ति:** लाभार्थियों को अन्य सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से बिजली कनेक्शन और नल का जल प्राप्त होने लगा है। इन सुविधाओं ने दैनिक जीवन स्तर में सुधार किया है और कठिन परिश्रम को कम किया है।

6. **नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प:** टिकाऊ ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर लालटेन और रूफटॉप सिस्टम पेश किए गए हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली प्रदान करते हुए पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करता है।
7. **गुणवत्तापूर्ण घरों के लिए कौशल निर्माण:** पीएमएवाईजी के तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम से कुशल राजमिस्त्री की कमी का समस्या दूर हो रही है, गुणवत्तापूर्ण आवास सुनिश्चित किया जा रहा और ग्रामीण आजीविका मिल रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा समर्थित, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने **25.11.2025 तक 3,75,265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है और 3,02,377 राजमिस्त्रियों को प्रमाणित किया है।**
8. **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं के नाम पर या पति-पत्नी के साथ संयुक्त रूप से घर के स्वामित्व को प्रोत्साहित करके, पीएमएवाई - जी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। **नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) की अध्ययन रिपोर्ट (2019)** में कहा गया है कि यह दृष्टिकोण भारत के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में योगदान देता है, विशेष रूप से महिला-पुरुष समानता और निरंतर सशक्तिकरण का समर्थन करके एसडीजी 5ए को आगे बढ़ाने में।

ग्रामीण आवास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी

आधुनिक तकनीक ने ग्रामीण आवास वितरण में एक नया आयाम जोड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल का उपयोग करके निगरानी तेज हो गई है, धोखाधड़ी की रोकथाम सशक्त हो गई है, और कार्यान्वयन पहले से अधिक विश्वसनीय हो गया है। ये नवाचार सुनिश्चित करते हैं कि बनाया गया प्रत्येक घर वास्तविक है और प्रत्येक लाभार्थी सत्यापित है।

1. **अनुशंसा प्रणाली:** एआई मॉडल अपलोड की गई तस्वीरों से दीवारों, छतों, दरवाजों और खिड़कियों जैसी घरों की विशेषताओं की पहचान करते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर, सिस्टम अनुमोदन के लिए सबसे उपयुक्त अंतिम तस्वीर को चुनता है और केवल

वास्तविक और पूर्ण घरों को अंतिम रूप से चुनकर उसके पूर्ण हो जाने को सुनिश्चित करता है।

2. **विसंगति का पता लगाना और धोखाधड़ी की रोकथाम:** मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एक ही इलाके में घरों की तस्वीरों के साथ दूसरे घरों की तुलना करते हैं। यदि समानताएं पाई जाती हैं, तो सिस्टम दोहराव या धोखाधड़ी रिपोर्टिंग को रोकने के लिए अलर्ट उठाता है। यह संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने का सुरक्षा उपाय है।
3. **चेहरा प्रमाणीकरण और ईकेवाईसी:** लाभार्थियों को आधार के जरिए, एआई-सक्षम चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र परिवारों को ही सहायता प्राप्त हो और डेटाबेस की विश्वसनीयता मजबूत हो। **आवास+ 2024 मोबाइल ऐप** केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से विकसित 3डी हाउस डिजाइन जैसी नवीन सुविधाओं के साथ आधार फेस ऑथेंटिकेशन को एकीकृत करके लाभार्थी की पहचान में पारदर्शिता को और बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी और अनुसंधान का यह संयोजन लाभ के वितरण में सटीकता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
4. **जीवंतता का पता लगाना:** लाभार्थी सत्यापन के दौरान पलक झपकने और गति का पता लगाने जैसी उन्नत सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। ये जांच पुष्टि करती हैं कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया लाइव और वास्तविक है, जो प्रतिरूपण या दुरुपयोग को रोकती हैं।

आगे का रास्ता

आने वाले वर्ष व्यापक ग्रामीण आवास प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक चरण का प्रतीक होंगे चरण I और II के तहत स्वीकृत 3.90 करोड़ घरों में से 2.99 करोड़ घरों का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है, यह कार्यक्रम 2029 तक 4.95 करोड़ घरों के अपने संचयी लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति पूरी कवरेज के लिए मंच तैयार करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक पात्र परिवार के पास एक स्थायी घर होगा।

पीएमएवाई-जी भारत के सबसे प्रभावशाली ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। आवास वितरण को गरिमा, सशक्तिकरण और सुविधाओं से जोड़कर, इसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। 2029 के लिए एक स्पष्ट रोडमैप के साथ, यह योजना **ग्रामीण भारत में "सबके लिए आवास"** की सोच को मूर्त रूप देती है।

संदर्भ:

ग्रामीण विकास मंत्रालय:

<https://pmayg.dord.gov.in/netiyHome/Home.aspx>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=2151276>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201070®=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=2092893®=3&lang=2#:~:text=PMAY%2DG%20is%20not%20just,dedication%20to%20holistic%20rural%20development.&text=by%20PIB%20Delhi->

[,The%20Ministry%20of%20Rural%20Development%20is%20committed%20to%20achieving%20the,of%20%E2%82%B93%2C06%2C137%20crore](https://www.pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=2092893®=3&lang=2#:~:text=PMAY%2DG%20is%20not%20just,dedication%20to%20holistic%20rural%20development.&text=by%20PIB%20Delhi-)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS245_Gd0dcP.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU473_bCgMMw.pdf?source=pqals

[https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1576_qYDA7Q.pdf?source=pqars#:~:text=\(a\)%20&%20\(b\);,%2C%20and%20female%2Dheaded%20households](https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1576_qYDA7Q.pdf?source=pqars#:~:text=(a)%20&%20(b);,%2C%20and%20female%2Dheaded%20households)

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2075171®=3&lang=2#:~:text=Celebrating%20Awaas%20Diwas%202024:%20Empowering,Pradhan%20Mantri%20Awaas%20Yojana%2DGrami>

<https://www.youtube.com/watch?v=vgRkpqs4u5I>

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एके/एम